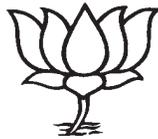


सरकार के घोटालों ने बढ़ाई महंगाई

- ◆ l ųkek Lojkt
- ◆ v#.k tų/yh



Hkkj rh; turk i kVhZ

प्रकाशकीय

संसद के बजट-सत्र में 25 फरवरी को दोनों सदनों में "देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी" के मुद्दे पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान भाजपा सांसदों ने केन्द्र सरकार पर बेलगाम महंगाई को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।

चर्चा की शुरुआत करते हुए लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने इस मसले पर संप्रग सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कम उत्पादन, सूखा, किसानों को अधिक लाभ और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतें बढ़ने के जो कारण बताए हैं, उनमें से कोई भी सच नहीं है बल्कि गेहूं, चावल, दाल और चीनी घोटाले हुए हैं उससे दाम बढ़े हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने संप्रग सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर निष्क्रियता दिखाई है और इस पर काबू पाने के लिए समय रहते कोई उपाय नहीं किए।

हम इस पुस्तिका में श्रीमती सुषमा स्वराज एवं श्री अरुण जेटली द्वारा महंगाई के मुद्दे पर दिए गए भाषणों को प्रकाशित कर रहे हैं ताकि संप्रग सरकार का जनविरोधी चेहरा बेनकाब हो सके।

çdk' kd
Hkkj rh; turk i kVhZ
11] v' kksd jk&M]
ubZ fnYyh&110001
ekp] 2010

महंगाई रोकने में सरकार असफल

& I kke Lojkt

अध्यक्षा जी, पिछले पांच वर्षों में आज नौवीं बार, महंगाई पर चर्चा हो रही है। मई 2004 में यू.पी.ए. की सरकार सत्ता में आई थी और मई 2004 के बाद, दिसम्बर 2004 में ही महंगाई पर पहली चर्चा हो गई और तब से लेकर वर्ष 2004, 2005, 2006, 2007 और वर्ष 2008 में लगातार यह चर्चा होती रही। वर्ष 2006 में तो तीन बार चर्चा हुई। मैं सारी तिथियां निकाल कर लाई हूँ। दिनांक 9-12-2004 को चर्चा हुई, 16-08-2005 को चर्चा हुई, 2006 में 22 मई को चर्चा हुई, 27 जुलाई को चर्चा हुई और 30 नवम्बर को चर्चा हुई। एक साल में तीन बार। 15 मई, 2007 को चर्चा हुई, 16-04-2008 को चर्चा हुई और 15वीं लोक सभा आने के बाद भी 3 अगस्त, 2009 को चर्चा हुई और अब यह नौवीं बार चर्चा हो रही है।

अध्यक्ष महोदया, यह केवल उन चर्चाओं के आंकड़े हैं, जो स्ट्रक्चर्ड 193 के तहत हुई हैं। इसके अलावा, कॉलिंग-अटेंशन यानी ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाई गई, स्पेशल मेशन के माध्यम से उठाई गई, उनमें से मैंने किसी को इसमें शामिल नहीं किया है। ये केवल 193 के नोटिसेस के तहत चर्चाएं हुई हैं, उन चर्चाओं का जिफ्र मैं कर रही हूँ, लेकिन इन चर्चाओं का नतीजा क्या हुआ— “मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की।”

“महोदया, मैं कल के आंकड़े लेकर आई हूँ। हर छः महीने बाद, सांसद उन्हें चेताते रहे, हर छः महीने के बाद सांसद महंगाई के बारे में अपनी व्यथ-कथा यहां कहते रहे, लेकिन दाम आसमान छूते रहे। मैं कल के बाजार भावों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। उस दिन भाई मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि प्रतिशत में मत बोलो कि 20 प्रतिशत महंगाई बढ़ गई या 10 प्रतिशत महंगाई बढ़ गई, क्योंकि कोई समझेगा नहीं। कौन सी चीज कितने में मिल रही है, यह बताओ। ठेठ शुद्ध भाषा में, देहाती भाषा में ये आंकड़े मैं लेकर आई हूँ। इन्हें मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहती हूँ। आटा 20 रुपए किलो, चावल 25 रु. किलो, अरहर दाल 90 रु.

किलो, मूंग छिलका 85 रु. किलो, मूंग साबुत 87 रु. किलो, मूंग धुली 90 रु. किलो, उड़द दाल 84 रु. किलो, सरसों का तेल 87 रु. किलो, चाय पत्ती 270 रु. किलो, चीनी 42 रु. किलो, नमक 12 रु. किलो, हल्दी 140 रु. किलो, लाल मिर्च 205 रु. किलो, धनिया 200 रु. किलो, जीरा 200 रु. किलो, प्याज 20 रु. किलो, मटर 20 रु. प्रति किलो, बीन्स 40 रु. किलो, भिंडी 30 रु. किलो, घीया 40 रु. किलो, बैंगन 30 रु. किलो और अदरक 80 रु. किलो।

अध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने किन चीजों के दाम आपके सामने रखे हैं, ये शुद्ध रूप से केवल वे चीजें हैं, जिन्हें गरीब खाता ही खाता है। मैंने दाम रखे हैं आटे और चावल के, मैंने दाम बताए हैं दालों और मसालों के, मैंने दाम गिनाए हैं तेल और सब्जियों के और मैंने दाम गिनाए हैं चाय पत्ती और चीनी के। इनमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो अमीर की डाइनिंग टेबल पर सजती हो। दूध, फल मक्खन आदि किसी का इसमें नाम नहीं है। ये उन चीजों के दाम हैं, कम से कम जिन्हें खाने का हक गरीब को मिलना चाहिए। दो समय की रोटी, रोटी या चावल के साथ, एक दाल और एक सब्जी के साथ खाने का हक तो है और दो समय की चाय, चीनी डालकर। रोटी या चावल, एक दाल या एक सब्जी से खाने के लिए आटा चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, मसाले चाहिए और तेल चाहिए और वह भी सरसों का, मैंने कोई देशी घी के दाम नहीं गिनाए हैं। दो समय की चाय, चाय पत्ती और चीनी के साथ। उस चाय में भी दूध नहीं होगा, काली चाय है, लेकिन वह भी आज गवारा नहीं है। ये दाम इस चीज को बताते हैं कि दो समय की रोटी, एक दाल या एक सब्जी के साथ या दो समय की काली चाय चीनी के साथ आज गरीब को नसीब नहीं है। इन दामों के साथ अगर नसीब हो सकती हो तो आप मुझे बता दीजिए।

अध्यक्षा जी, मुझे दुख हुआ जब मैंने महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ते हुए उन्हें सुना। उन्होंने कीमतों पर दबाव की बात तो की, लेकिन उससे पहले एक वाक्य से सरकार ने अपनी पीठ यह कहकर थपथपायी कि हम अपनी खाद्य सुरक्षा को किसी प्रकार के संकट से मुक्त रखने में समर्थ रहे हैं। ...यह राष्ट्रपति जी ने कहा है। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हम किसी भी प्रकार के संकट से अपनी खाद्य सुरक्षा को मुक्त रखने में समर्थ रहे हैं। पूरे देश के गरीब पर संकट गहराया हुआ है। उसकी खाने की थाली पर संकट है, उसके दो समय के भोजन पर संकट है, लेकिन सरकार इन सबसे बेखबर अपनी पीठ थपथपाकर कह रही है कि हम खाद्य सुरक्षा को किसी भी तरह

के संकट से मुक्त रखने में समर्थ रहे हैं।

अध्यक्षा जी, ऐसा कहते हैं कि किसी भी रोग का इलाज करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है, उसका सही परीक्षण होना, उसका सही डायग्नोसिस होना। अगर डायग्नोसिस सही कर लिया जाए तो इलाज की दिशा तय हो सकती है, लेकिन जिस सरकार का आकलन अपने बारे में यह है कि खाद्य सुरक्षा पर कोई संकट ही नहीं है, तो वह इलाज क्या करेगी? कीमतों पर दबाव की जो बात उन्होंने की है, उसके चार कारण गिनाए हैं – पहला कारण घरेलू उत्पादन में कमी, दूसरा कारण विश्व स्तर पर चावल, दाल और तेल के बढ़े हुए मूल्यों के कारण कीमतों में बढ़ोत्तरी होना अपरिहार्य, तीसरा कारण किसानों को खरीद कीमतों का अधिक भुगतान और चौथा कारण ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि। ये चार कारण गिनाए हैं और मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि ये चारों कारण निराधार हैं, सत्य से परे हैं। ये कैसे सत्य से परे हैं, मैं आपके सामने यह बताना चाहती हूँ। पहला कारण कहते हैं कि घरेलू उत्पादन में कमी है। मेरे पास कृषि मंत्री जी का बयान है, जो उन्होंने इकॉनामिक एडीटर्स कान्फ्रेंस में वर्ष 2008-09 में बोलते हुए कहा था।

"As you know, the year 2008-2009 was a very good year for agriculture with an all-time high production of 233.38 million tones of food grains ..."

वर्ष 2008-09 में कृषि मंत्री ने यह कहकर अपनी पीठ थपथपायी थी। उन्होंने आर्थिक संवाददाताओं के सम्मेलन में बोलते हुए कहा था कि देश में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। 233.38 यानी लगभग 234 मिलियन टन खाद्यान्न देश में पैदा हुआ, यह स्वयं कृषि मंत्री जी ने आर्थिक संवाददाताओं को बताया। जहां तक वर्ष 2009-10 का सवाल है, पी.आई.बी. ने अभी यह आंकड़ा रिलीज किया है। यह पी.आई.बी. की रिलीज है जिसमें उन्होंने सेकेंड एडवांस एस्टीमेट देते हुए बताया है कि 216.85 यानी लगभग 217 मिलियन टन खाद्यान्न इस साल पैदा होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब 233 मिलियन टन रिकार्ड प्रोडक्शन होता है, तो 216 मिलियन टन सामान्य से थोड़ा ही तो कम होगा। अगर 233 मिलियन टन आल टाइम हाई है, तो 217 मिलियन टन सामान्य से थोड़ा ही तो कम है।

अध्यक्षा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे समय में चालीस मिलियन टन अनाज कम पैदा हुआ था। आप एक सूखे की ओट में पूरी जिम्मेदारी से बरी हो जाना चाहते हैं, हर समय सूखे की दुहाई देते हैं। अध्यक्ष

जी, हमने चार-चार प्राकृतिक आपदायें झेली थीं। हमने उड़ीसा के झंझावात का सामना किया था, हमने गुजरात के भूकंप का सामना किया था, हमने प्रलयकारी बाढ़ का सामना किया था, हमने भीषण सुखाड़ का सामना किया था। तब चालीस मिलियन टन अनाज कम पैदा हुआ था, लेकिन बाजार में एक रूपया भी दाम नहीं बढ़ने दिया था। हमने क्या किया था, हमने गोदामों के ताले खोल दिए थे। हमने अनाज के बदले काम का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। राज्य सरकारों को कहा था कि मुफ्त अनाज देंगे, आप अनाज के बदले काम प्रारंभ करिए, लेकिन लोगों को भूखा मत मरने दीजिए। हमने गोदामों के ताले खोले थे।... वे तमाम लोग जो गेहूं से आटा, मैदा, सूजी बनाते थे, हम लोगों ने उन्हें सस्ते दाम पर अनाज बेचा था और अन्त्योदय के साथ एक नई अन्नपूर्णा योजना शुरू की थी जिसमें 10 किलोग्राम से कोटा बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया था और दाम 2 रुपये और 3 रुपये किलो कर दिए थे। यही कारण है कि हमारा भी छः वर्ष का शासनकाल था, लेकिन केवल एक बार प्राइस राइज़ पर चर्चा हुई थी। मैं आंकड़ा लेकर आई हूँ। 27.04.2000 को सोनिया जी का नोटिस था। यह उस समय स्वयं नेता, प्रतिपक्ष थीं। लेकिन एक बार भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि इन्हें नोटिस देकर यह कहना पड़े कि हम कीमतों की वृद्धि पर चर्चा करना चाहते हैं, मूल्य वृद्धि पर चर्चा करना चाहते हैं, महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं। 27.04.2000 को एक नोटिस था जिसके ऊपर चर्चा हुई और वह भी खाद्यान्न की कीमतों पर नहीं था, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थीं, तब चर्चा हुई थी। छः वर्ष में एक बार प्राइस राइज़ पर डिस्कशन और पांच वर्ष में नौ बार, यह अपने आपमें एक तुलना बताती है। क्यों? क्योंकि दाम घटाओ और कोटा बढ़ाओ।

महोदया, मैं चाहूंगी कि यह विषय जितना गंभीर और संवेदनशील है, कम से कम हम उतनी ही शाइस्तगी से इस विषय पर चर्चा करें और सुनें। वह शायद उन गरीबों के प्रति एक हमदर्दानी व्यवहार होगा। जो व्यवहार हो रहा है, वह उनके प्रति हमदर्दी नहीं दिखा रहा है। इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगी कि इस चर्चा को हम शान्ति और गंभीरता से होने दें। जो गंभीरता इसमें अपेक्षित है, वह गंभीरता सदन में झलके तो उसे और कोई राहत मिले न मिले, इतनी राहत जरूर मिलेगी कि उसका दर्द यहां कह दिया गया है, उसकी व्यथा यहां बता दी गई है।... मैं कह रही थी कि दाम घटाओ और कोटा बढ़ाओ, यह हमारा प्रबंधन था, इसलिए कभी प्राइस राइज़ पर चर्चा नहीं हुई और दाम बढ़ाओ और कोटा घटाओ, यह इनका प्रबंधन है, इसलिए

नौ-नौ बार चर्चा हुई।...यह आंकड़े देकर मैंने आपको बताया कि पहला कारण जो बताया गया कि घरेलू उत्पादन में कमी के कारण महंगाई बढ़ रही है, वह कारण सच नहीं है।

दूसरा कारण आपने यह कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाल, चावल और तेल के भाव बढ़ गये, इस कारण महंगाई बढ़ गयी।

अध्यक्षा जी, मैं यहां फ्यूचर ट्रेड्स, अमेरिका के आंकड़े लेकर आयी हूँ। मैंने ये आंकड़े नेट से निकाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बुशल के तौर पर मात्रा तय की जाती है और डॉलर की करेंसी में रुपया तय किया है, पैसा तय किया जाता है। मैंने अपने देशवासियों को समझाने के लिए बुशल को किलोग्राम में परिवर्तित किया और डॉलर को रुपयों में परिवर्तित किया। डॉलर का रेट कल 46.2 रुपये था और उसी दर से इसको परिवर्तित किया। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव बताती हूँ। गेहूँ, दिसम्बर 2008 में 11 रुपये प्रति किलो था और फरवरी 2010 में घटकर 8 रुपये 51 पैसा रह गया। ...चावल, जनवरी 2008 में 14 रुपये 59 पैसे था और फरवरी 2010 में 14 रुपये 45 पैसे, यह बढ़ा नहीं, बल्कि 14 पैसे घटा। मक्का, जून 2008 में 12 रुपये 16 पैसे प्रति किलो थी और फरवरी 2010 में 6 रुपये 71 पैसे प्रति किलो बिकी। सोयाबीन का तेल, फरवरी 2008 में 69 रुपये प्रति किलो था और फरवरी 2010 में 37 रुपये प्रति किलो है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दाम हैं, जो मैंने आपके सामने रखे हैं।

अध्यक्षा जी, दूसरा जो कारण बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिरे, तो वह भी सच नहीं है। तीसरा कारण यह बताया गया कि किसानों को समर्थन मूल्य अधिक दिया। अब क्या समर्थन मूल्य अधिक दिया? वर्ष 2007-08 में साढ़े आठ रुपये प्रति किलो और वर्ष 2008-09 में दस रुपये प्रति किलो और वर्ष 2009-10 में दस रुपये अस्सी पैसे प्रति किलो समर्थन मूल्य दिया गया। क्यों शरद भाऊ यही आंकड़े हैं—प्रति किंवटल साढ़े आठ सौ रुपये फिर एक हजार रुपये प्रति किंवटल और फिर एक हजार अस्सी रुपये प्रति किंवटल? लेकिन उपभोक्ताओं को किस भाव में खिलाया? जब साढ़े आठ रुपये समर्थन मूल्य था, तो आटा 15 रुपये प्रति किलो बिका। जब 10 रुपये समर्थन मूल्य था, तो आटा 17 रुपये किलो बिका। जब 10 रुपये 80 पैसे प्रति किलो का समर्थन मूल्य था, तो आटा 20 रुपये किलो बिका। आप कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य के कारण महंगाई बढ़ी। अगर समर्थन मूल्य से डेढ़ या दो रुपये ज्यादा पर चीज बिकती, तो मैं आपके इस तर्क को मान

लेती कि आपने साढ़े आठ रुपये किसान को दिये, इसलिए वह 11 रुपये बिकना ही था। लेकिन दूर-दूर तक कोई रिश्ता किसानों को दिये हुए समर्थन मूल्य और बाजार में बिकने वाले दाम का नहीं है।

अध्यक्षा जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे यहां कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है और कल्याणकारी राज्य का मतलब था कि किसानों से महंगा खरीदो और उपभोक्ता को सस्ता खिलाओ और बीच का अनुदान दो। उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं, लेकिन हम किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं देते और उपभोक्ता को महंगा खिलाने की मार मार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि किसानों के समर्थन मूल्य के कारण महंगाई बढ़ी है।

शरद भाऊ, जहां तक किसान का सवाल है, तो आप एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से ले लेते हैं। अगर आपने किसानों का समर्थन मूल्य साढ़े आठ से दस रुपये अस्सी पैसे किया, तो अभी चार दिन पहले आपने पच्चीस रुपया प्रति बोरा यूरिया का दाम बढ़ाकर उसके दूसरे हाथ से पैसा लेने का काम किया है। ...किसान के द्वारा खरीद की जाने वाली हर वस्तु, हर उपकरण महंगा है। वह एक चीज बेचता है, लेकिन बाकी सारी चीजें खरीदता है। अगर गेहूँ का उत्पादन करता है, तो गेहूँ बेचता है। चावल उत्पादन करता है, तो चावल बेचता है, लेकिन बाकी सारी चीजें—दालें, चाय, चीनी आदि सारी चीजें खरीदता है या नहीं? किसानों के समर्थन मूल्य और उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ने वाली मार में किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए आपका यह तर्क भी सही नहीं है कि किसानों के समर्थन मूल्य के कारण दाम बढ़े हैं।

चौथा कारण आपने बताया है कि गरीबों की आय में वृद्धि हुई है क्योंकि ग्रामीण विकास कार्यक्रम तेजी से चल रहे हैं। मैं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की चर्चा यहां विस्तार से नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि उससे विषयांतर हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ, अभी पीछे से आवाज आई कि नरेगा तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। ...नरेगा से छला हुआ मजदूर दोहरी मार सह रहा है — महंगाई की मार भी सह रहा है और भ्रष्टाचार की मार भी सह रहा है। गरीबों की कौन सी आय वृद्धि की बात आप कहते हैं? मैं कहती हूँ कि अगर नरेगा पूरा चले, सही चले, एक भी पैसे का पिलफरेज न हो तो 100 दिन का कारोबार, 100 रुपए प्रतिदिन की बात आपने कही है। पूरे 100 दिन उसे रोजगार मिले, 100 रुपए प्रतिदिन पगार मिले, तो साल

के 10,000 रूपए होते हैं यानी 850 रूपए प्रति महीना। 850 रूपए की आय को आप गाना गाकर, ढोल पीटकर कहते हैं कि गरीबों की आय में वृद्धि हो गयी? 850 रूपए की आय उसकी जेब में आएगी और वह भी तब आएगी अगर 100 दिन पूरा रोजगार मिले और 100 रूपए प्रतिदिन पगार मिले। हालात यह है कि जॉबकाडर्स बने हैं, न 100 दिन का रोजगार मिल रहा है, न 100 रूपए पगार मिल रही है।

अध्यक्षा जी, महंगाई बढ़ने के जो चार कारण राष्ट्रपति अभिभाषण में गिनाए गए हैं कि घरेलू उत्पादन में कमी हुई है, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं, किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य मिला है, गरीबों की आय में वृद्धि हुई है, इसलिए महंगाई बढ़ी है, ये चारों कारण अनुचित हैं, चारों कारण निराधार हैं और ये चारों कारण असत्य हैं। महंगाई के कारण कौन से हैं, यह मैं बताती हूँ। महंगाई के चार कारण हैं। इसे मैं आपके सामने बताती हूँ कि वे चारों कारण घोटाले हैं, गेहूँ घोटाला, चावल घोटाला, दाल घोटाला, चीनी घोटाला और इसीलिए इसे हम महंगाई नहीं, महंगाई का महाघोटाला कहते हैं।

अध्यक्षा जी, मैंने घोटाला शब्द का प्रयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है। मैं एक-एक घोटाले के आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूँ। जहां तक गेहूँ आयात घोटाले का सवाल है, आपने वर्ष 2007-08 में गेहूँ के लिए 8.50 रूपए समर्थन मूल्य दिया। शरद भाऊ मैं आपका ध्यान चाहूंगी। 8.50 रूपए समर्थन मूल्य दिया आपने, लेकिन उसी साल आपने गेहूँ आयात किया 14.82 रूपए प्रति किलो के हिसाब से यानी हमारे यहां के किसान को 850 रूपए का दाम और विदेशी किसान को 1482 रूपए का दाम, 632 रूपए प्रति क्विंटल आपने ज्यादा दाम विदेश के किसानों को दिया। आपने गेहूँ कौन सा मंगाया, ऐसा लाल गेहूँ जो आदमी तो क्या जानवर भी खाने से मना कर दे। लाल रंग के गेहूँ की रोटी जब थाली में रखी जाती थी, तो आदमी को भ्रम होता था कि शायद पत्नी ने गुड़ की रोटी बनाई है।

वह बहुत खुशी-खुशी मुंह में डालता था और मुंह में डालते ही उसे इतनी बकबकी होती थी कि वह थूकता फिरता था। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि यह कैसी रोटी है, तो वह कहती थी कि जैसा गेहूँ मिला है, वैसा ही गेहूँ की रोटी बनाई है। यह गेहूँ 14 रूपए 82 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से आयात किया गया था।

मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगी कि यह उनकी अपनी

मानसिकता को दर्शाता है इसलिए आप चुप रहें। गरीब सुन रहा है कि यह नाटक उसके साथ ये रच रहे हैं या हम कर रहे हैं।

अध्यक्षा जी, विदेश से 14 रूपए 82 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से लाल गेहूँ मंगवाया और वहीं बस नहीं कर गए। शरद भाऊ यहां बैठे हैं। अगले साल फिर 19 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से दस लाख मीट्रिक टन अनाज मंगाने का प्रस्ताव आया, लेकिन देश में किसानों का इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया कि इन्हें वह निर्णय रद्द करना पड़ा, वरना 19 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से फिर आयात हो रहा था। यह तो हुआ इस घोटाले का एक पहलू, मैं अब इस घोटाले का दूसरा पहलू बताना चाहती हूँ। घोटाले का दूसरा पहलू यह है कि सन् 2007-2008 में यह कह दिया गया कि गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध है, बैन कर दिया गया है।

लेकिन आरटीआई के तहत एक क्वैरी लगी। उसमें एक व्यक्ति ने पूछा कि गेहूँ का कोई निर्यात इन सालों में हुआ है तो उसका जवाब आया कि वर्ष 2007-2008 में भी निर्यात हुआ और वर्ष 2008-2009 में भी हुआ। इसी तरह वर्ष 2009-2010 में भी निर्यात हुआ। मैं अगर आपको बताऊं कि किस दाम पर निर्यात हुआ था, तो आप हैरान हो जाएंगे। आप 14 रूपए 82 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से आयात करते हो, फिर 19 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से आयात करने का प्रस्ताव करते हो, लेकिन वर्ष 2007 में दस रूपए एक नए पैसे के हिसाब से निर्यात हुआ। इसी तरह वर्ष 2008-2009 में 13 रूपए दो नए पैसे के हिसाब से निर्यात हुआ। वर्ष 2009-2010 में जब हमारे देश में आटा 20 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है, तो उसका 12 रूपए 51 पैसे के हिसाब से निर्यात हुआ। आप कहते हैं कि घोटाला नहीं है। अगर यह घोटाला नहीं है तो फिर क्या है? आपका अपना उपभोक्ता, भारतवासी, बाजार से 20 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से आटा खरीद रहा है और भारत की सरकार प्रतिबंध के बावजूद 12 रूपए 51 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से वर्ष 2009-2010 में निर्यात कर रही है। यह घोटाला नहीं तो और क्या है।

अध्यक्ष महोदया, मैंने कहा था कि गेहूँ के बाद चावल में भी घोटाला हुआ है। अब मैं चावल के निर्यात में जो घोटाला हुआ, वह बताती हूँ। चावल को दो किस्मों बासमती और गैर बासमती में बांटा जाता है। तय किया गया कि वर्ष 2007-2008 में गैर बासमती चावल का निर्यात नहीं होगा।

क्योंकि दाम घरेलू बाजार में बढ़ रहे थे। अध्यक्ष महोदया, लोगों की

आंखों में धूल झोंककर गैर-बासमती को बासमती बताकर निर्यात किया गया। यह पहला घोटाला था।

दूसरा घोटाला, अफ्रीकी देशों की मदद करने के नाम पर गैर-बासमती चावल का निर्यात भी खोला गया और वह निर्यात सरकारी कंपनियों के द्वारा नहीं प्राइवेट व्यापारियों के द्वारा करवाया गया। मुझे कष्ट से कहना पड़ता है कि जिनकी मदद के लिए वह चावल निर्यात किया गया था, वह उन लोगों तक नहीं पहुंचा, बीच समुद्र में दूसरी तरफ सरका दिया गया, दूसरी तरफ चला गया। आपका अपना देश भूखा मर रहा

आपने अपने लोगों के मुंह का निवाला छीना और जिनकी मदद के लिए, जिनकी भूख मिटाने के लिए भेजा, उन तक पहुंचाया भी नहीं और बीच में ही लाभ बनाकर ले गये, प्रॉफिट बनाकर ले गये। यह घोटाला नहीं तो क्या है?

तीसरा घोटाला दालों का हुआ। ...अध्यक्ष जी, दालों का घोटाला तो त्रासदी से भरा हुआ है। घरेलू बाजार में दालों के भाव आसमान छू रहे थे। दाल 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया, 42 रुपया, 50 रुपया किलो हुई और अभी कल के दाम मैंने आपको बताए कि दाल 90 रुपया किलो है। दालों का आयात किया गया, आयात की छूट दी गयी लेकिन मुझे आपको बताते हुए दुःख होता है कि आयात की हुई दालें बंदरगाह पर पड़ी रहीं, व्यापारियों ने वहां डैमरेज देना स्वीकार किया लेकिन दालों को बाजार में लाना इसलिए स्वीकार नहीं किया कि दाम और बढ़ने वाले हैं और वहां से तब उठाएंगे जब हमें इसके दाम का लाभ तिगुना-चौगुना मिलेगा। मुझे ज्यादा दुःख इस बात का है कि इस आयात में स्टेट एजेंसियां एसटीसी, पीईसी, एनएसी, एमएमटीसी और नैफेड इस अपराध में शामिल थीं। उन दिनों 'हैडलाइन्स टूडे' ने एक स्टोरी की थी। उनकी एक खोजी टीम कोलकाता बंदरगाह पर पहुंची थी और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कोरपोरेशन में लदी हुई बोरियां उन्होंने दिखाई थीं जबकि लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, उन्हें खाने के लिए दालें नहीं मिल रही हैं। गरीब की एक मात्र प्रोटीन दाल होती है लेकिन वह आयातित माल इस इंतजार में पड़ा हुआ था कि कब दाम बढ़ें और उन्हें बाजार में लाया जाए। यह दालों का घोटाला था।

अध्यक्ष महोदया, चौथा घोटाला चीनी का है। चीनी का पूरा का पूरा कारोबार सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। आप उनकी मुस्कराहट में गरीब का दर्द देखो। गरीब का बेरौनक चेहरा देखो, इन्हें मुस्कराने दो। यह मुस्कराते

नहीं तो दाम बढ़ते क्यों? अध्यक्ष महोदया जी, चीनी की फैक्ट्रियां लगाने का लाइसेंस सरकार देती है, गन्ने की कीमत सरकार तय करती है, लेवी में जो चीनी ली जाती है उसका दाम तय करने के साथ-साथ सरकार उसे खरीदती भी है और चीनी के आयात-निर्यात की नीति भी सरकार तय करती है। इस पूरे का ज्ञान माननीय शरद भाऊ से ज्यादा किसी को नहीं है, वे चीनी साम्राज्य के मालिक हैं, वे देश के चीनी सम्राट हैं। मैं माननीय शरद भाऊ जी से पूछना चाहती हूं कि आपको मालूम है कि चीनी के उत्पादन का साईकल तीन वर्ष का होता है। वर्ष 2006-2007 में इस देश में चीनी का रिकार्ड उत्पादन 28.3 मिलियन मीट्रिक टन हुआ।

चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ और चीनी के दाम कम हुए, तो गन्ना किसानों को कम लाभ मिला। इसका नतीजा यह हो सकता था कि गन्ना किसान अगले वर्ष गन्ने की जगह कुछ और बोए। वैसे भी जब चीनी की इतनी बहुतायत हो गई, तो कोई भी दूरदर्शी कृषि मंत्री यह कहता कि मैं बफर स्टॉक जमा कर लूं, क्योंकि कल को अगर चीनी की देश में कमी होगी, तो बफर स्टॉक से निकाल कर दे दूंगा। लेकिन बफर स्टॉक नहीं बनाया और चीनी को निर्यात करने की छूट दे दी। इतना निर्यात हुआ कि देश में ही चीनी की कमी हो गई। जब देश के लोग त्राहि-त्राहि करने लगे कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, तो ओजीएल पर उन्हीं कंपनियों को आयात करने की छूट दे दी। जब निर्यात किया तो निर्यात करते समय उन्हें अपनी तरफ से सरकारी खजाने से एक्सपोर्ट असिसटेंस भी दी कि निर्यात करो और ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग के हम कुछ पैसा दे देते हैं, वह भी ले लो। जब घर में कोहराम मचा तो कहा कि अब चीनी का आयात कर लो। मैं आपको बताना चाहती हूं कि ओजीएल के तहत फिर आयात शुल्क की छूट दे दी कि ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट कर लो। ऐसा चीनी मिल मालिकों को भी कहा, प्राइवेट व्यापारियों को भी कहा और स्टेट एजेंसियों को भी कहा।

अध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहती हूं कि एक ही समय में देश में चीनी का आयात भी हो रहा था और निर्यात भी हो रहा था। एक समय ऐसा भी आया, वह दृश्य देखने लायक था कि कांगड़ा बंदरगाह पर दो जहाज एक साथ खड़े थे। एक जहाज चीनी ले कर आया था और दूसरा जहाज चीनी ले कर जा रहा था। महोदया, आप आंकड़ों को सुनकर हैरान होंगी कि जो चीनी बेची जा रही थी, वह साढ़े बारह किलो के हिसाब से बेची जा रही थी और जो चीनी खरीदी जा रही थी, वह छत्तीस रुपए प्रति किलो की दर से

खरीदी जा रही थी। अगर ये आंकड़े गलत हैं, तो शरद भाऊ बता दें। एक ही समय पर चीनी का निर्यात और आयात जारी था। आप जानती हैं कि इसका क्या परिणाम हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि 33 चीनी मिलें, जो स्टाक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जिनका लाभांश त्रैमासिक तौर पर तय किया जाता है, उन 33 कम्पनियों का लाभ अक्टूबर से दिसम्बर, 2008 में कुल मिला कर 30 करोड़ रुपए था, जो अक्टूबर से दिसम्बर, 2009 में बढ़ कर, आप अनुमान लगाइए कि कितना हो सकता है, वह प्रोफिट 30 करोड़ से बढ़ कर 901 करोड़ रुपए हो गया। अगर आप प्रतिशत लगाओ तो 2900 प्रतिशत उनका मुनाफा बढ़ गया। देहाती भाषा में सौ कम तीन हजार प्रतिशत उनका मुनाफा बढ़ गया। इसीलिए अध्यक्ष महोदया मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चीनी भले ही मेरे और आपके लिए कड़वी हो, चीनी भले ही गरीब की चाय से गायब हो गई हो, लेकिन उन चंद चीनी मिल मालिकों ने अपने वारे न्यारे कर लिए और सात पुशतों का पैसा जमा कर लिया। उस मुनाफे में किसका कितना हिस्सा है, यह मुझे नहीं मालूम है, मैंने इसकी खोज नहीं की है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इसकी खोज होनी चाहिए।

ये चार घोटाले मैंने आपके सामने रखे हैं और चारों ऐसी चीजें हैं, जो गरीब की थाली से गायब हैं। आटा, दाल, चावल, चीनी, इन चारों चीजों के घोटाले मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं आपसे मांग करती हूँ कि एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो इन चारों घोटालों का पर्दाफाश करे और बताए कि यह आयात और निर्यात जो बार-बार खुल रहे थे, आखिरकार इसके पीछे मामला क्या था।

ये कहेंगे डॉयलाग और नाटक की बात कहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक फिल्म में किसी ने धर्मेन्द्र से पूछा कि आप क्या काम करते हो, उन्होंने कहा – इधर का माल उधर करता हूँ और उधर का माल इधर करता हूँ। अगर सच पूछें तो महंगाई केवल इस कारण से हुई है कि सरकार इधर का माल उधर कर रही है और उधर का माल इधर कर रही है। जब इधर फायदा होता है तो आयात खोल देती है और जब उधर फायदा होता है तो निर्यात खोल देती है। मेरी मांग है कि इधर-उधर करने की जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि जेपीसी गठित हो ताकि मैंने जो चार घोटाले सामने रखे हैं, वह इनका पर्दाफाश करे। यह कमेटी सब लोगों के सामने लाए कि महंगाई के क्या कारण हैं, वे चार कारण नहीं हैं या ये चार कारण हैं।

महोदया, अब मैं खाद्य सुरक्षा की पोल खोलना चाहती हूँ। राष्ट्रपति अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति से कहलवाया गया कि हम अपनी खाद्य सुरक्षा को दीर्घावधि के लिए सुनिश्चित तब कर पाएंगे जब कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करेंगे। इसके नीचे लिखा था कि हमारी सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार कहती है हम खाद्य सुरक्षा कानून बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप महामहिम राष्ट्रपति के मुंह से असत्य भाषण क्यों करवाते हैं? मेरे पास पिछली बार का भी अभिभाषण है, नौ महीने पहले जून की बात है, उसमें कहा गया धेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नामक नया कानून बनाने का प्रस्ताव करती है। आज ये कृतसंकल्पता पर आ गए जबकि तब प्रस्ताव किया था। इसमें लिखा है कि 'प्रस्ताव करती है जो एक ऐसे ढांचे के लिए सांविधिक आधार मुहैया कराएगी जिसमें सभी के लिए खाद्य सुरक्षा का आश्वासन होगा। ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक परिवार तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह 25 किलोग्राम गेहूँ और चावल प्राप्त करने का कानूनन हकदार होगा। इस विधान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक व्यवस्थित सुधार लाने के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा।'

पिछली बार का अभिभाषण है। आपने इस देश के बारे में महामहिम राष्ट्रपति के मुंह से कहलवाया कि आप एक ऐसा कानून लाएंगे जिस कानून में 25 किलोग्राम गेहूँ या चावल प्रति माह तीन रुपए किलो के आधार पर देंगे। आज नौ महीने बीत गए हैं, लेकिन क्या हुआ? चाहिए तो यह था कि इस अभिभाषण में यह आता कि हमने उस कानून में क्या प्रगति की है, हमने कानून का प्रारूप तैयार करवा लिया, हम इस सत्र में इसे लेकर आ रहे हैं या आपने पहले पारित करवा लिया होता लेकिन आप यह न करवाकर कृतसंकल्पता पर आ गए। अंग्रेजी में इसका मतलब है हिंदी में इसका मतलब है हम कृतसंकल्प हैं। आप कैसे कृतसंकल्प हैं? मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के चार स्तंभ होते हैं और आप चारों स्तंभों की उपेक्षा कर रहे हैं। आप कैसे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे? आप पूछेंगे कि चार स्तंभ कौन से हैं? सबसे पहला स्तंभ गरीबी के सही आंकड़े हैं। देश में गरीबों की कितनी संख्या है यह पता लगाना चाहिए। दूसरा स्तंभ अच्छा उत्पादन है। इसका मतलब है उत्पादन बढ़े। तीसरा स्तंभ पर्याप्त भंडारण है। हमारे गोदाम भरे रहें। चौथा स्तंभ प्रभावी वितरण है। जब तक ये चार

आयाम, पाये या स्तंभ मजबूत नहीं होते तब तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती है। अब मैं इस सरकार के बारे में बताती हूँ कि इन चार स्तंभों को क्या मजबूती दी है जिससे चारों स्तंभ लड़खड़ा रहे हैं। जहां तक गरीबों की संख्या का सवाल है, वर्ष 2004-05 की जनसंख्या के आधार पर गरीबों की संख्या जानने के लिए चार कमेटियां और एजेंसियां बनाईं। चारों एजेंसियों ने अलग आंकड़े दिए और वर्ष 2004-05 की जनसंख्या को आधार बनाया। पहला आंकड़ा योजना आयोग का आया, इसके अनुसार इस देश में 25.7 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसके बाद एक और कमीशन, नेशनल कमीशन फार इन्ट्रिन्योर्स इन अनऑर्गेनाज्ड सैक्टर का गठन किया गया।

क्यों बसुदेव दा इन्होंने ऐसा किया था? उसका आंकड़ा आया कि 77 प्रतिशत लोग इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उसके बाद इन्होंने एक सुरेश तेंदुलकर कमेटी गठित की। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने ग्रामीण भारत की गरीबी अलग निकाली और शहरी भारत की गरीबी अलग निकाली और कुल मिलाकर आंकड़ा 37.2 प्रतिशत दिया। उन्होंने कहा कि 37.2 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय तस्वीर में आ गया। उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनायेंगे और चूंकि हमें कार्यक्रम चलाना है, हम गरीबी के आंकड़े देंगे और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक एन.सी. सक्सेना कमेटी बना दी। उसने गरीब भारत के आंकड़े निकालकर कहा कि इस देश में ग्रामीण भारत के पचास प्रतिशत लोग गरीब हैं। आज तक आप यह तय नहीं कर पाये कि गरीबी मापने का आधार क्या होगा, आज तक आप यह तय नहीं कर पाये कि इन आंकड़ों में से आपका कौन सा आंकड़ा मान्य होगा। इस तरह से आपका पहला स्तम्भ ही लड़खड़ा गया। अब गरीबी मापने का नया आधार क्या आ रहा है कि गरीब कितनी कैलोरी खाता है? अध्यक्ष महोदया, मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस गरीब का पेट पीठ से सटा हुआ है, उसके पेट में क्या कैलोरी टटोलते हो? उसके पेट में नहीं, उसके माथे पर लिखा है कि वह गरीब है। उसके घर से गरीबी बोलती है। उसके बदन के चीथड़े कपड़े गरीबी बोलते हैं। उसका पेट टटोलने की जरूरत नहीं है।

मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछली बार का जो इनका राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उसमें आपने कहा था कि आप बीपीएल के आंकड़े लायेंगे, उसके लिए ग्राम सभा या शहरी निकाय को माध्यम बनायेंगे। आपने कहा था कि ग्राम सभा बैठकर तय करेगी कि हमारे गांव में गरीब कौन हैं, शहरी

निकाय तय करेंगे, ताकि आपत्ति दर्ज कराई जा सके, अगर कोई गलत आंकड़ा आ जाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि गरीबी का आंकड़ा तय करने के लिए क्या ग्राम सभा की एक भी मीटिंग हुई, क्या शहरी निकाय ने गरीबी का एक आंकड़ा भी दिया? जब आपको यही पता नहीं है कि खाद्य सुरक्षा कितने लोगों की तय करनी है, आपको यही मालूम नहीं है। अगर घर में एक गृहिणी को यदि पति कह दे कि शाम को मेरे कुछ मित्र आ रहे हैं, आप उनके लिए खाना बना लेना तो वह पहला सवाल पूछती है कि कितने लोग होंगे? अगर वह कहे कि दस लोग आयेंगे और 25 आ जाएं तो उसकी फजीहत होनी ही है। वह 10 में से 15 को खिला देगी, 16 को खिला देगी, लेकिन 25 को कैसे खिलायेगी? यह साधारण कॉमन सैन्स है कि अगर आप खाद्य सुरक्षा तय करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह तय करिये कि आपको कितनों को खिलाना है। आपके गरीबों का आंकड़ा क्या है? लेकिन आज तक यह सरकार न गरीबी के आंकड़े तय कर पाई, न गरीबी मापने का आधार तय कर पाई तो इनका पहला स्तम्भ पूरी तरह लड़खड़ा गया।

दूसरा स्तम्भ मैंने कहा था— अच्छा उत्पादन, बढ़ा हुआ उत्पादन। शरद भाऊ, बढ़ा हुआ उत्पादन कब होगा, बढ़ा हुआ उत्पादन तब होगा, जब कृषि योग्य भूमि बढ़ेगी, ज्यादा रकबे में खेती होगी, यह साधारण सी बात है। लेकिन आपके अपने कृषि मंत्रालय के आंकड़े हैं कि इस साल कृषि योग्य खाद्यान्न का रकबा आठ प्रतिशत घटा है। मेरे पास स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। स्टैंडिंग कमेटी ने आपके द्वारा दिये गये आधार पर कहा है, मैडम, मैं वह पढकर सुनाना चाहती हूँ —

"The Committee observes that the area under foodgrains has declined by 8 per cent from 680.99 lakh hectares in 2008-09 to 626.47 hectares in 2009-10".

680 लाख हैक्टेअर से घटकर 626 लाख हैक्टेअर में खाद्यान्न उग रहा है। आप कह रहे हैं कि 2009-10 में प्रोडक्शन कम हुआ। यह स्वाभाविक बात है, कम रकबे में अगर आप खाद्यान्न बोयेंगे तो कम पैदा होगा, ज्यादा रकबे में अगर आप खाद्यान्न बोयेंगे तो ज्यादा पैदा होगा। जब आपका रकबा ही घट रहा है। आपकी भूमि खेती से निकल कर गैर खेती चीजों में जा रही है, एसईजैड के लिए जा रही है, बाकी चीजों के लिए जा रही है तो आपके यहां उत्पादन कैसे बढ़ेगा, यह मैं आपसे पूछना चाहती हूँ? जो दूसरा स्तम्भ है। आपने इस बार राष्ट्रपति से कहलवाया कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने

के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ानी जरूरी है।

केवल उत्पादन नहीं, उत्पादकता चाहिये। यह उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? जिस जमीन में आज खेती नहीं हो रही है यानी जो असिंचित है उसे आप सिंचित करते हैं, उसे खेती योग्य बनायेंगे, ज्यादा भूमि में खाद्यान्न बोयेंगे, तभी उसका उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादन और उत्पादकता का आपस में सीधा रिश्ता है। आप जितनी ज्यादा भूमि कृषि योग्य बनाते जायेंगे, खाद्यान्न उगाते जायेंगे, आपका उतना ज्यादा उत्पादन बढ़ता जायेगा लेकिन इसका उलटा हो रहा है। आपका रकबा कम हो रहा है और खेती खिसक रही है। जहां तक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का सवाल है, उसमें आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। अगर कृषि की उत्पादकता को आगे बढ़ाना है तो गुजरात सरकार का मॉडल आपके सामने है। अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि गुजरात की अर्थव्यवस्था कभी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी लेकिन उसने कृषि विकास दर को 9.6 प्रतिशत पर लाकर रख दिया है। यह बात न मैं कह रही हूँ, न आडवाणी जी मोह में कह रहे हैं और न बी.जे.पी. के नेता कह रहे हैं। यह सर्टिफिकेट इस देश के जाने-माने अर्थशास्त्री दे रहे हैं। ये अर्थशास्त्री हैं – सर्वश्री तुषार शाह, अशोक गुलाटी, पी. हेमन्त और गंगा श्रीधर। इन लोगों ने एक पेपर लिखा है जो इकोनोमिक और पोलिटिकल वीकली में छपा है। उसमें शीर्षक था— "Secrets of Gujrat agrarian miracles after 2000" सन् 2000 के बाद गुजरात में कृषि चमत्कार का रहस्य। ये अर्थशास्त्री भाजपाई नहीं है। इन्होंने डा. एम.एस आहलुवालिया की प्रशंसा में एक पेपर लिखा था। लेकिन यह चमत्कार कैसे हुआ? सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात में वह भूमि जो बंजर थी, उस बंजर भूमि को सिंचित करके वहां रोड इनफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दूरदृष्टि दिखाकर जो खेती करवाई है, उससे कृषि उत्पादकता बढ़ी है। उसके कारण यह चमत्कार हुआ और गुजरात ने कृषि विकास दर 9.6 प्रतिशत हासिल की है। अगर सरकार कृषि में उत्पादकता बढ़ाना चाहती है तो एक राज्य का मॉडल आपके सामने तैयार है लेकिन उसके लिये दूरदर्शिता चाहिये, इच्छा शक्ति चाहिये, उसके लिये सही नीतियां चाहिये और उन नीतियों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन चाहिये जो इस सरकार में चारों की कमी दिखाई देती है।

अध्यक्ष महोदया, खाद्य सुरक्षा का तीसरा स्तम्भ लड़खड़ा रहा है क्योंकि खाद्यान्न पहले के बजाय घटा है जबकि खाद्य सुरक्षा के लिये उत्पादकता

बढ़नी चाहिये। मैंने जैसा कहा कि तीसरा स्तम्भ पर्याप्त भंडारण का होना चाहिये। जहां तक भंडारण का सवाल है, शरद जी जानते हैं क्योंकि कंज्यूमर अफेयर्स के वह मंत्री हैं। हमारी भंडारण की प्रमुख संस्था एफ.सी.आई. के पास 25.7 लाख मीट्रिक टन की कवर्ड और 28 लाख मीट्रिक टन का अनकवर्ड कैपेसिटी है। एफ.सी.आई के पास जो अपने गोदाम हैं या जो किराये पर लिये हुये हैं, उनमें हमारी टोटल कवर्ड और अनकवर्ड कैपेसिटी भंडारण की है। जो अनाज बाहर रखा जाता है, वह बारिश के कारण सड़ता है, जो अंदर रखा जाता है, वह पुराना होकर सड़ता है। शरद जी को याद होगा कि जब मैं राज्य सभा की सदस्य थी, उनसे एक सवाल किया था। हमारे यहां परम्परागत अनाज की हैंडलिंग मैनुअल की जाती है जब कि विश्वभर में मिकेनाइज्ड हैंडलिंग हो रही है। मैनुअल और मिकेनाइज्ड हैंडलिंग में अंतर यह है कि जब बोरियों का लदान किया जाता है तो पल्लेदार आता है, एफसीआई के गोदाम में बोरियां रख देता है। जब नई आवक होती है तो उसके ऊपर नई बोरियां रख देता है और जब नया अनाज आता है तो उसके ऊपर रख दिया जाता है। जब सार्वजनिक वितरण के लिये अनाज निकालते हैं तो ऊपर की बोरियां सब से पहले निकालते हैं।

जो नया अनाज आया, वह निकल गया और पुराना अनाज वहीं बना रहा। फिर खरीफ की फसल आयी, फिर लदान आ गया, फिर पीडीएस के लिए नया अनाज निकल गया और पुराना अनाज पड़ा रहा। मैकेनाइज्ड हैंडलिंग में उल्टा है, वहां कन्वेयर बैल्ट की तरह चलता है। जब अनाज की बोरी निकलती है तो सबसे पहले नीचे की बोरी निकलती है, उसके बाद ऊपर की बोरी निकलती है। नीचे का अनाज निकलता जाता है और ऊपर की अनाज की बोरी नीचे आती जाती है।

महोदया, मैं आपको बता रही थी कि मैकेनाइज्ड हैंडलिंग और मैनुअल हैंडलिंग का यह फर्क है कि मैकेनाइज्ड हैंडलिंग में पुराना अनाज निकलता जाता है और नयी बोरी नीचे जाती रहती है। इससे अनाज सड़ता नहीं है और वह बचा रहता है। हमारे यहां मैनुअल हैंडलिंग की जो प्रथा है, उसके कारण नयी बोरियां निकलती जाती हैं और पुरानी बोरियां सड़ती जाती हैं। मैं अनाज की पुरानी बोरियों के सड़ने की बात ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। एक आरटीआई की क्वेरी श्री देवाशीष भट्टाचार्य ने लगायी थी। उसने पूछा था कि एफसीआई हमें बताए कि क्या उनका कोई खाद्यान्न नष्ट हुआ है? उस आरटीआई की क्वेरी का जवाब आया था कि हां, हमें 10 लाख टन खाद्यान्न

नष्ट करना पड़ा है, क्योंकि वह अनाज सड़ गया है। उस दिन मुलायम सिंह यादव जी जो बात कह रहे थे कि चूहें अनाज खा रहे हैं, वह बात गलत नहीं है, वाकई चूहें अनाज खा रहे हैं। जो अनाज नीचे पड़ा है।

महोदया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस क्वेरी में बताया गया कि 10 लाख टन खाद्यान्न नष्ट कर दिया गया। उसके बाद यह प्रश्न मेरे सहयोगी श्री अनंत कुमार ने सदन में उठाया। उस समय शरद जी ने कहा था कि हम इस सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, लेकिन आज तक सिस्टम दुरुस्त नहीं हुआ है। यह हमारी भंडारण की स्थिति है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा अनाज सड़ रहा है तो आपके पास जो आंकड़े हैं कि इतना बफर स्टॉक है, वह अनाज नहीं है, वह भुना हुआ अनाज है। वह अनाज बुरा हो गया है, जब आप उसे निकालेंगे तो वह खाने योग्य नहीं होगा, वह केवल समुद्र में फेंकने योग्य होगा। आपका पर्याप्त भंडारण का स्तंभ भी लड़खड़ा रहा है। ...

महोदया, खाद्य सुरक्षा का चौथा स्तंभ प्रभावी वितरण है। मैंने जो चार स्तंभ गिनाये थे, उनमें चौथा स्तंभ है प्रभावी वितरण। यहां शरद जी कह सकते हैं कि वितरण व्यवस्था तो राज्यों के जिम्मे हैं, उसमें आप हमें क्या कहना चाहती हैं, मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ। वितरण व्यवस्था राज्य के जिम्मे जरूर है, लेकिन इस वितरण के लिए बांटा जाने वाला खाद्यान्न केंद्र सरकार देती है।

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के आँकड़ों में बहुत बड़ा विवाद है। मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ। हमारे मुख्य मंत्री ने लिखकर आपको दिया कि हमारे यहाँ 42 लाख गरीब हैं। आप कहते हैं कि आपके मुताबिक 21 लाख गरीब हैं। जब आधा माल देंगे तो आधा ही तो बाँटेंगे। 42 लाख लोगों के लिए जरूरत है और 21 लाख के मुताबिक मिल रहा है, उस पर आप कहते हैं कि वितरण व्यवस्था प्रभावी बने। कैसे राज्य वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाएँ? हमारे यहाँ तो और दुखदायी बात है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अच्छा गेहूँ पैदा करता है, एशिया का सबसे अच्छा शरबती गेहूँ पैदा करता है। लेकिन आप हम पर दबाव डालकर कहते रहे कि लाल गेहूँ बाँटो। हमने कहा कि लाल गेहूँ आपके यहाँ से आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ेगी, जबकि हमारे यहाँ अपने गेहूँ का भंडारण हो रहा है। जो मजदूर जाकर खेत में अच्छा शरबती गेहूँ बो रहा है, उसको अगर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाल गेहूँ खिलाएँगे तो वह कितनी बददुआ देगा? लेकिन आप कहते हैं

कि आप उसको लाल गेहूँ खिलाओ क्योंकि हम आपको लाल गेहूँ दे रहे हैं; हम 21 लाख का देंगे और आप 42 लाख को खिलाओ; आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो शाबाशी देना चाहती हूँ भाजपा शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों को, जो अपने ही खजाने पर बोझ डालकर वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाया। मध्य प्रदेश में दो रुपये किलो और तीन रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ-चावल बाँटा जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ तो सबसे आगे निकल गया – एपीएल को दो रुपये किलो, लेकिन एक रुपया किलो के हिसाब से बीपीएल को छत्तीसगढ़ में चावल खिलाया जा रहा है। हर महीने की सात तारीख को 35 किलो चावल का बोरा एक रुपया किलो की दर से मात्र 35 रुपये में हमारे सारे लोग खड़े होकर बँटवा देते हैं और 35 रुपये में वह राशन लेकर अपने घर चला जाता है। किसान को हम समर्थन मूल्य से ज्यादा बोनस दे रहे हैं। धान का बोनस 36 रुपये करने दिया, गेहूँ का बोनस 100 रुपये मध्य प्रदेश ने दिया। हम कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं। हम किसान को अपने खजाने से बोनस दे रहे हैं और गरीब को अनुदान देकर सस्ता अनाज खिला रहे हैं। यह हमारी वितरण व्यवस्था है, लेकिन आपकी वितरण व्यवस्था में खाद्य सुरक्षा के चारों के चारों पाये लड़खड़ा रहे हैं।

अध्यक्षा जी, एक तरफ तो महंगाई की मार से गरीब मर रहा है और दूसरी ओर जले पर नमक छिड़कने का काम इस सरकार के मंत्री कर रहे हैं। कभी शरद जी का बयान आता है जिसमें वे कहते हैं कि मैं कोई ज्योतिषी थोड़े ही हूँ जो बताऊँ कि महंगाई कब कम होगी। अरे शरदभाऊ, किसी बुरे ग्रह के कारण महंगाई नहीं आई है जो ज्योतिषी की जरूरत हो। महंगाई आपकी सरकार की गलत नीतियों के कारण आई है और इसीलिए सरकार से पूछा जाता है कि नीतियों में सुधार कब करोगे, बताओ – महंगाई कम होगी कि नहीं, और कम होगी तो कब होगी? इनकी एनसीपी की एक मैगज़ीन है – राष्ट्रवादी, जिसमें कहते हैं कि चीनी तो खानी ही नहीं चाहिए, उससे डायबिटीज़ हो जाती है। ऐसे ऐसे बयान आते हैं। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने कहा था कि हिन्दुस्तान के लोगों ने ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया है, इसलिए महंगाई हो गई है। उसको भारतीय शैली में इनकी सरकार के एक मंत्री ने कहा कि गरीब चूँकि दो वक्त रोटी खा रहा है, इसलिए महंगाई हो गई है। अगर आप हमारे घावों पर मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम उस पर नमक छिड़कने का काम तो मत करिये।

अध्यक्ष जी, सरकार में इतनी अंतर्कलह चल रही है कि एक दूसरे के माथे

पर ठीकरा कैसे फोड़ा जाए, सब इसी कवायद में लगे हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि शरदभाऊ के माथे ठीकरा फोड़ो और बरी हो जाओ। फिर वे कहते हैं कि कलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। वे प्रधान मंत्री को सामूहिक जिम्मेदारी याद दिलाते हैं कि प्रधान मंत्री आप हैं, मैं तो केवल कृषि मंत्री हूँ। लेकिन प्रधान मंत्री का दृष्टिकोण अलग है, क्योंकि प्रधान मंत्री अर्थशास्त्री भी हैं। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह में दुविधा चलती है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत यह समझाता है कि महंगाई बढ़ती हुई विकास दर की द्योतक होती है। इसलिए जब देश में महंगाई बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उन्हें वाहवाही मिलती है। वे जाकर कह सकते हैं कि देखो – inflation is an indicator of growth. मैं जो कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ विकास दर बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि इंडिया में इनफ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन जब प्रधान मंत्री के तौर पर वे सोचते हैं तो उन्हें चिन्ता सताती है। वे दोनों दुविधाओं में फँसे हुए हैं। लेकिन आज प्रधान मंत्री यहाँ नहीं हैं। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि प्रधान मंत्री जी, अब अर्थशास्त्र में भी नये मुहावरे आ रहे हैं।

इन नये मुहावरों को समझिए। अभी कुछ दिन पहले मेरी भूटान के राजा से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि उनके पिता, जो कि के-फोर कहलाए जाते हैं, उन्होंने और कोस्टारिका ने मिलकर एक नया मुहावरा दिया है कि जीडीपी की टर्म में बात मत करो, जीएनएच की टर्म में बात करो। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स सही आंकड़ा नहीं देता है। जीएनएच का मतलब है, ग्रास नेशनल हेपीनेस और यही बात मैं प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को बताना चाहती हूँ कि महंगाई किसी ओर की बढ़ रही है, विकास दर किसी ओर की बढ़ रही है, इसलिए दोनों में तालमेल नहीं है। विकास दर तो उनकी बढ़ रही है जो 30 करोड़ से 901 करोड़ के हो गए। आप उन्हें दाल एक हजार रुपये किलो भी खिला दो, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यह गरीब जो नित्य कुआं खोदता और नित्य पानी पीता है, महंगाई की मार इस पर पड़ रही है। इसलिए जीडीपी की टर्म में बात मत करो, जिस दिन जीएनएच की टर्म में सोचना शुरू कर दोगे, जिस दिन गरीब के आंसू आपको दिख जाएंगे, उस दिन आपकी नीतियां सही हो जाएंगी। अर्थशास्त्री के नाते जब आप सोचते हैं तो आप इन नीतियों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। गरीब रो रहा है। उसके पास दो समय की रोटी नहीं है और जब त्यौहार आता है तो

आंसू नौ-नौ की जगह सौ-सौ हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहती हूँ, वह यहां नहीं बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व बैठा है, यूपीए की चैयरपर्सन बैठी हैं। यूपीए की चैयरपर्सन पर एक अन्य ढंग की जिम्मेदारी भी आयी है। वह सरकार को संचालित करते हुए अपनी तरफ से भी निर्देश दे सकती हैं और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपने प्रधानमंत्री जी को समझाइए और यह चार पंक्तियां आपको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन आप गरीब के आंसू देखना शुरू कर दोगे उस दिन अपने आप महंगाई समाप्त हो जाएगी, उस दिन ये घोटाले भी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये चार पंक्तियां हैं—

किसी मजबूर की मजबूरियों को सोचकर देखो,
 प्रेम को झोपड़ियों के बीच खोजकर देखो।
 अन्नर इंसानियत को धरती पर बुलाते हो,
 किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछकर देखो।

■

Synopsis

During the past five years, this is the ninth occasion when we are taking up discussion on the issue of price rise under Rule 193. Besides, we have taken up this issue through Calling Attention and Special Mentions. We have been highlighting the troubles and travails caused by price rise in this Parliament that the prices are sky-rocketing. The basic food consumed by a common man comprises of flour, rice, pulses, mustard oil, tea, sugar, salt, spices and the vegetables which are getting beyond their reach. It is ironic that the poor are being denied the right of having two square meals.

Her Excellency, the President, in her Address has referred to the burden of price rise. The four reasons attributed to the price rise are stated to be shortfall in domestic production, the enhanced prices of rice, pulses and oil in the international market, payment of increased procurement prices to the farmers and increase in the income in the rural areas. I think all the four reasons are

unfounded and beyond truth, since the Agriculture Minister has himself stated while speaking in the Economic Editors' Conference that the year 2008-09 has been a good year for agriculture with the agriculture production touching 233.38 million tonnes of foodgrains. The P.I.B. has stated in its second Advanced Estimates for 2009-10, that we are going to have agriculture production of approximately 217 million tonnes this year and it will be a little less than the average production. It may be mentioned that we were faced with the shortage of 40 million tonnes of foodgrains during our term. Now, this Government seeks to escape from its responsibility under the cover of drought. We had to face cyclone in Orissa, earthquake in Gujarat, devastating floods and severe droughts during our tenure. Though we had a shortfall of 40 million tonnes of foodgrains, however, we did not allow the prices to rise in the market. We had opened the locks of our godowns. We had launched the Food for Work Programme. A new scheme, Annapurna, beside Antyodaya was also started whereby the quota of foodgrains was raised from 10 kg to 35 kg to be sold at Rs. 2 and Rs. 3 per kg. This is the reason that during the tenure of our six years' rule, not a single discussion on price rise was taken up. Our priority was to bring down the prices by increasing foodgrain quota, whereas this Government is acting just opposite. They allow the prices to rise and cuts down foodgrain quota. The first reason for price rise is stated to be shortfall in domestic production which is not true. The second reason has been attributed to the price rise of pulses, rice and oil in the international market, while in the international market, the price of wheat has come down from Rs. 11 in December 2008 to Rs. 8.51 in February, 2010. Likewise, the price of rice came down from Rs. 14.59 in January, 2008 to Rs. 14.45 in February, 2009. Hence, the prices have fallen in the international market. The third reason is stated to be the enhanced payment of Minimum Support Price to the farmers. As per the data available, The MSP was Rs. 8.50 per kg. in 2007-08, Rs. 10 per kg. in 2008-09 and Rs. 10.80 per kg in 2009-10. However, the consumers got the flour at the rate of Rs. 15 per kg. It was

being sold at the rate of Rs. 17 per kg when the MSP was Rs. 10. Similarly, it was being sold at the rate of Rs. 20 per kg when the MSP was Rs. 10.80. The Government says that the increase in MSP has led to price rise. This plea could be accepted if the margin between the MSP and the market price has been Rs. 1.50 to Rs. 2. However, there is no relation between the MSP being paid to the farmers and the retail prices prevailing in the market. So far as the farmers are concerned, on one hand they are given relief, on the other hand the same is snatched from them. The increase of Rs. 25 in Urea price is a recent instance. The prices of all the inputs purchased by the farmers have gone up. The fourth reason advanced by the Government for the price rise is stated to be the increased income of the poor, as the Rural Development Programmes are stated to be implemented at an accelerated pace. Today, the labour is doubly hit by the price rise as well as the corruption. A labour gets Rs. 10,000 per annum if he gets the wages of Rs. 100 per day for hundred days in a year. This works out to be Rs. 850 per month. Now, the Government takes credit that the income of poor has gone up.

Here I would like to analyse and put forth the four reasons of price rise which are the root-cause. These include wheat scam, the rice scam, the pulse scam and the sugar scam. As far as wheat import scam is concerned, in the year 2007-08 the MSP was Rs. 8.50 per kg while it was imported at the rate of Rs. 14.82 per kg. It means that the foreign farmers were paid Rs. 632 per quintal more. The second aspect of this scam is that the wheat export in 2007-08 was banned. However, the wheat was allowed to be exported in 2007-08, 2008-09 and 2009-10. Wheat was exported at the rate of Rs. 10.01 per kg in 2007. Likewise, it was exported at the rate of Rs. 13.02 per kg. While the flour in the country is being sold at the rate of Rs. 20 per kg in 2009-10, it is being exported at the rate of Rs. 12.51 per kg. Likewise, a scam has also taken place in case of rice. It was decided that non-basmati rice would not be exported in 2007-08. However, taking the people for a ride, non-basmati rice was exported under the

cover of basmati rice.

In the same manner, in the name of helping out the African countries, the export of non-basmati rice was also allowed. But the consignment did not reach them and was diverted elsewhere. The third scam related to pulses. When the prices of pulses were sky-rocketing in the domestic market, the decision to import pulses was taken. But the imported pulses were kept lying at the ports. The traders were ready to pay the demurrage but they did not lift the stock in the hope of earning 3-4 times profit when the prices go up in the domestic market. The fourth scam relates to sugar. The whole sugar affairs are controlled by the Government. It is the Government which grants licenses to the open sugar mills, then MSP is also decided by the Government, the levy sugar is also procured by the Government and the price for the same is fixed by it. The policy to import or export sugar is also formulated by the Government itself. The sugar production cycle spans over a period of three years. The year 2006-07 witnessed a record production of sugar to the tune of 28.3 million metric tonne and prices of sugar came down as a result of which sugarcane growers got less price for their produce. When there was record production of sugar, any foresighted Agriculture Minister could think of creating the buffer stock. But, buffer stock had not been created and export of sugar was allowed as a result of which shortage of sugar was created in the country. But, we were exporting sugar at the rate of Rs. 12.50 per kg and importing it at the rate of Rs. 36 per kg. In the process, the sugar mill owners have been benefitted. I demand from the Government that a Joint Parliamentary Committee should be constituted to enquire all the said scams.

Her Excellency, the President mention that we will be able to ensure our food security in the long term only when we continuously endeavour to increase agricultural productivity. It is also mentioned in the Address that the Government is committed to enact a law to ensure food security. Why are the government compelling the President to make untrue promises? Last year, in the month of June, Her Excellency, the President had mentioned in her Address

that her Government would bring a proposal to enact the National Food Security Act. But today, they are saying that the Government is committed to bring this Bill. There are four pillars to ensure Food Security and the Government is undermining all these four pillars. The first pillar requires the accurate figures about poverty, second elates to production, third is sufficient storage and the fourth one is effective distribution system. Food security cannot be ensured if these pillars are not strengthened. As far as the number of poor is concerned, population of 2004-05 should be made the basis for it. For this purpose, four committees have been constituted. As per Planning Commission, 25.7 per cent people of the country are living below the poverty line. According to the National Commission for Entrepreneurs in Unorganised Sector, 77 per cent people of this country are living below poverty line. Then, Suresh Tendulkar Committee was constituted. As per this Committee, 37.2 per cent people are living below poverty line.

Again, the Ministry of Rural Development has constituted N.C. Saxena committee. As per this Committee, 50 per cent people of rural India are living below poverty line. Therefore, if the Government is sincere to ensure food security, first of all the number of poor people should be calculated accurately. But, till date, this Government is unable to determine neither the number of poor nor to fix the criteria of measurement of poverty. Second pillar is good production. Production can be increased only if cultivable land area is increased. But as per figures given by Ministry of Agriculture this year area under cultivation has declined by 8 per cent. According to the Standing Committee, the area under foodgrain cultivation has declined by 8 per cent from 680.99 lakh hectares in 2008-09 to 626.47 lakh hectares in 2009-2010. If area under foodgrain continues to shrink, production will certainly come down. Not only production but productivity should also be increased. There is direct correlation between production and productivity. The Government has not taken any step to increase productivity.

The Government should emulate the model of the Gujarat

Government for increasing productivity. The economy of Gujarat has never been dependent on agriculture but the growth rate of agriculture in Gujarat has increased to 9.6 per cent. The Government of Gujarat has provided irrigation facilities and road infrastructure in Saurashtra, Kuch, and North Gujarat as a result of which agricultural productivity has increased in the State. This pillar of food security is also crumbling because food production has declined. Productivity should be increased to ensure food security. The third pillar of food security is adequate storage capacity. The Food Corporation of India is the main food storage agency of the Government and it has 25.7 lakh metric tonne covered and 28 lakh metric tonne uncovered storage capacity. The foodgrains stored in the open gets spoiled. Handling of foodgrains in the country is being done manually whereas all over the world it is done in a mechanized manner. The main difference between mechanized handling and manual handling is that in the former, old sacks of foodgrains are replaced by fresh stock and in manual handling, fresh stock is continued to be stocked out whereas the old stock is spoiled. The fourth pillar of foodgrains management is effective distribution system. Undoubtedly, food distribution system is the responsibility of the State Governments but foodgrains for this system is provided by the Union Government. There is a huge difference between the figures with the States and the Centre.

The Chief Minister of Madhya Pradesh has written to the Centre that there are 42 lakh poor people in the State but the Union Government says that as per their opinion, there are only 20 lakh poor people in the State. When the Union Government provides half of the requirement, the States have to distribute this allocation. The BJP ruled States have burdened their exchequer in order to strengthen their public distribution system. Wheat and rice are being distributed at the rate of Rs. 2 per kg and Rs. 3 per kg respectively in Madhya Pradesh. In Chattisgarh, rice is being distributed at the rate of Rs. 2 per kg to APL families and at the rate of Rs. 1 per kg to BPL families. On the one hand, poor

people are suffering due to rising prices, on the other hand the Minister of this Government is adding salt to injury. The Hon. Minister says that he is not an astrologer to forecast as to when the prices will start coming down. Prices are shooting up due to wrong policies of this Government. Hence, I want to ask the Government as to when the policies of the Government will be set right.

There is an inner conflict in the Government as to how to pass buck on one another. There is a great dilemma between an economist Manmohan Singh and the Prime Minister Manmohan Singh. As per the principle of economics, inflation is the sign of growth. However, when as Prime Minister, he ponders over the situation, he is a worried man. Then, new ideas are also getting coined. Today, the gross domestic product does not give a true picture. Now-a-days, gross national happiness has assumed relevance and this is what I want to bring home well this point to our Prime Minister, that the ill-effects of price rise are taking its toll on a large section of the society whereas the fruits of growth are being relished by a selected few. There is no coordination between the two. Hence, let us not talk in terms of GDP. The moment we start thinking in terms of GNH, the day we empathizes with the plight of poor, the policies of Government will be corrected and headed in the right direction. The day this Government is moved by the plight and tears of poor, the price rise will be checked and the scams will cease to take place.

■

Control inflation or quit

- Arun Jaitley

Sir, I am extremely grateful to you for having not only allowed this discussion but also having allowed this discussion to take place in preference to other Business of the House considering the vital importance of this issue. We have in the last few Sessions, Sir, been practically discussing this, almost in every Session, and the object really is that it is not merely the thrill or the pleasure that we get out of debating this issue, ideally we wanted a Parliamentary referendum on this issue, and that is why for the last two days we wanted to press for a discussion on a Resolution which involves voting. But, in view of the arrangement arrived at in the House, we once again want to draw the attention of the Government to a complete inaction of the Government on the kind of misery being inflicted on the people of this country by this unprecedented price rise, particularly the increase in the prices of food articles of this country. We find that despite the fact that we have been discussing it with almost every Session, prices have been on the increase. Apparently the gravitational principles do not seem to apply to the price management policy, as far as this Government is concerned. Because what happened in the last few months, if you look at the prices on the food front today, the situation seems to be far worse. But, before I go to the crux of the issue, I would like to make a brief comment whether this Government is taking serious steps as a part of its larger economic management, as far as this issue is concerned.

Sir, the Budget Session, which is the first Session every year, the principal Business, Sir, besides the policy of the Government and its performance enunciated in the Address of the President to

the Joint Session, also involves major decisions on the Economic Policy of the Government, be it the Budget, the Economic Survey or the Rail Budget. This exercise started yesterday. And, what happened yesterday itself if it seriously had to reflect upon the economic management of this country, it started by some kind of a comic exercise, which was not even a relief, as far as this country is concerned. This showed the lack of seriousness, as far as this Government is concerned on the economic management, Sir.

Sir, when I heard how Railways will run medical institutions, sports facilities, I was wondering what Mr. Ghulam Nabi Azad and Mr. Gill are going to do in the months to come. I recollect, Sir, that long ago, there used to be an advertisement of Tata Steel which used to state, "We also manufacture Steel". That seems to be the policy of some of these Ministries, particularly Railways, that this Government seems to be following because what was the concern, as far as the core issues are concerned, was absolutely marginal.

Now, if you translate the same approach to other departments of this Government--the Consumer Affairs Ministry, the Food and Agriculture Ministry--headed by our distinguished Shri Pawar, what was the approach of his party as far as the price management situation is concerned? His party has a journal called *Rashtra Vaadi*. The journal went on to make an editorial comment saying, 'So what if sugar prices in this country have risen? If you do not consume sugar or if you consume less sugar, you are not likely to die.'

Sir, medically what Brindaji says may be an appropriate comment for a person inflicted by problems on account of excessive consumption of sugar, but historically this was ridiculing the misery of the people. In fact, when we grew up in schools and colleges, the extreme example of ridicule to the misery of the people used to be Mary Anthony's comment, 'If you do not get bread, start eating cakes!' So, if sugar prices skyrocketed, thank God, you would not die by consumption of sugar, that is what the official journal of NCP editorially commented. But, the NCP, then

realising the embarrassment, at least tried to distance itself from the editorial.

But, another wise journal called the Congress Sandesh, yesterday made another editorial comment in its search for alibis for failure. The Congress Sandesh said yesterday, 'Besides the party's mouthpiece, Congress Sandesh has warned that carelessness in dealing with issues related to human feelings will cost us dearly. Some practical difficulties in coordination amongst the Prime Minister's Office and various Ministries are natural in coalition Governments.' Sir, I can only call it a confessional statement of this Government. It says that there is a 'natural' lack of coordination as far as the Prime Minister's Office is concerned and various Ministries of this Government are concerned, particularly in dealing with sensitive issues like price rise!

Sir, we see today a situation where there is only an attempt as far as the blame game is concerned. Is the Food, Agriculture and Consumer Affairs Ministry responsible for this? Is the Oil and Natural Gas Ministry responsible? Is the Prime Minister's Office not being able to coordinate? Ultimately, we survive in this Parliamentary democracy in a cabinet system. In a cabinet system, there is an element of collective responsibility. In a collective responsibility, the Prime Minister as the head of the Cabinet is more responsible than his other distinguished colleague. Sir, leadership is not the art of making compromises for the sake of coalitions. After all, leadership also involves an element of enforcing certain amount of discipline amongst all Ministers who hold office particularly on account of the pleasure of the President on which, in our democracy, is the pleasure of the Prime Minister. Therefore, we cannot live with a system where the Prime Minister's Office feels helpless and the party's mouthpiece says, 'We cannot help it, there is a lack of coordination'! This kind of indiscipline cannot be countenanced under any circumstances. As a result of which we must now have action as far as the Government is concerned on an important issue like price rise.

So, what do we find today? We are just emerging out of a

situation where the world faced recession. We also faced some element of global slow down. I am grateful for the Prime Minister that he is here. He is a very distinguished economist and he knows, perhaps, better than most of us. The normal principle is when there is a lack of economic activity, when consumers do not reach markets, when jobs are lost, when salaries are cut, when revenues are less, obviously money in the pocket of consumers is far less.

Therefore, globally when you are in a slowdown situation, prices are bound to come down and world over we saw almost negligible or negative rates of inflation as far as those items were concerned. But even during the slowdown period, food inflation was one factor, which in India continued to rise. We were also affected. There were sectors where people were losing jobs, the purchasing power of the consumer had gone down, there were salary cuts, there were pink slips which were being given, the traders were earning less, the manufacturers were not able to sell their products and despite inadequate or reduced economic activity and less money in the pocket of the consumer, which should have essentially led to prices coming down, we still had food prices going up. In the last few months, they have actually skyrocketed. The food price inflation in this country now moves between 17 and 19 per cent. What conclusions do we draw from this? Has this Government run completely out of ideas how to deal with the situation? Obviously, it has. Can't this Government anticipate shortages if there is a supply side problem and take action or pre-emptive action in time so that the shortages or inadequacies in the market could be addressed adequately? Is there a manipulation of policy in some fields or in some areas, which is contributing to the difficulties and miseries as far as this area is concerned? Or is this Government primarily involved in the exercise of finding alibis for its own failures and finding some reason or the other why the prices are going up, and, therefore, the Government itself is not responsible? Or is this Government merely adopting a 'do nothing' approach and when price cycle will globally change, hope-

fully, it will have some impact in India, and, therefore, prices in India will also come under some element of control? Sir, if we look at the latest figures, the Wholesale Price Index, which is not a representative price index because there is wide divergence between the Consumer Price Index, what the consumer actually pays, and the wholesale price index, today the increase is 8.56 per cent. Over the next month and a half, it is again anticipated to touch a double-digit inflation. Now this was something, which we used to witness ten or fifteen years ago and before that. Otherwise, we even had forgotten the use of phrase of 'double-digit inflation' in India. It has come back now and it came back last year. The price index for industrial workers is 14.9, agricultural workers 17.21, -- these are the percentages of inflation -- and for food prices it is 17 to 19 per cent. Let us look at the actual rise in food prices, which the consumer pays. I read a detailed article in the Times of India which actually elaborated that between the mandis and what the actually consumer buys in terms of vegetables and fruits from his retail shopkeepers, the price difference is several fold. Therefore, the 17 to 19 per cent inflation figure, which we are talking in terms of price in mandis, what the actual consumer buys from his retail shopkeeper, the Times of India says, is several times over and above that figure itself. Sir, now we are facing a situation where the Government's inability to control inflation is almost like unlegislated tax on the people. A large part of your income today is being spent on account of this unprecedented price rise.

If the quantum of increase goes unchecked -- as the way it is -- only in the vague hope that in future it will come down, it is going to cause immense amount of misery as far as the people are concerned. Sir, look at the December figures. If I just take some items, processed food-27 per cent increase, potatoes-17 per cent increase, onions-45 per cent increase, dal-45 per cent increase, cereals-14 per cent increase, Sir, if the Railway Budget provided some kind of a comic situation, I won't call it a relief...

Sir, yesterday evening, we saw another form of thrill or relief

in terms of a spectacular performance by Sachin Tendulkar, a double century. I think, at least in term of inflation, this Government is competing dal prices with Sachin Tendulkar. It has almost achieved a century. It has crossed a century as far as the dal prices are concerned. It has crossed a half century as far as sugar prices are concerned. This is the performance as far as this Government is concerned. Therefore, in search of this it starts looking for all forms of alibis. How do you deal with, 'what can I do?' Sir, we are told, "O, we had a drought this year and on account of drought this year we had 18 million tons less of food production. The kharif crop was badly affected and because it was 18 million less this year, prices are bound to go up, therefore, the drought situation affected the prices." This is the first alibi which is being given. So, I recollect more districts being affected, more uneven rainfall. The year was 2002 as against 18 million less of food grain production. The fall was 40 million tons and 40 million ton less of food grain production should have created havoc in the market. The Government had stocks. Stocks were off-loaded into the market. The consumer was protected and we ended the year with 3.4 per cent wholesale price index inflation. Now, the claim of this Government is that yes, we have adequate stocks. Well, then, you should have anticipated it. You should have repeated what happened in 2002 where the inadequacy of foodgrain production was 40 million tons less. You counted that drought situation, flooded the market with foodgrains so that the consumer is not affected. That is why we keep stocks in such large numbers. But, the management of food economy was entirely different. We are now told, 'well there is a lot of future trading which was started when the NDA was in power. The commodity exchanges came up'. Well, these are all experiments to be done when you are dealing with a surplus economy on foodgrain. If your population is rising, if your foodgrains increase and production is not adequate along with it and you have now transgressed in the year 2010 into an economy of shortages, you can't afford to have those experiments of a surplus economy when you are in a scarcity

economy and therefore, the Government should have anticipated the scarcity and gone in for a policy change because circumstances now have changed. You have four and a half lakh crores of future trading which takes place; the actual lifting is only one per cent of that. So, the balance 99 per cent is actually only future trading. Now, whether this also impacts inflationary expectations and has an impact on the price market is a fact that the Government had to consider.

Only 1 per cent is actually traded in terms of physical lifting. The rest of the lifting does not take place and it has taken place only on paper! Therefore, anticipate a situation of shortage and bring about policy changes as far as the Government's functioning is concerned. But, all this is something which the Government did not anticipate.

The third alibi I found was, let us start blaming the State Governments and put the ball in the court of the Chief Ministers. Also, suggestions were made that non-UPA Chief Ministers are not co-operating, you need to crackdown as far as hoarding is concerned, etc. You called the Conference of the Chief Ministers earlier this month. You circulated the data of raids and actions taken by the State Governments. But that entire data has a different story to tell. If you translate it into simple arithmetic, you will know that 83 per cent of the raids and searches took place in States which have non-UPA Chief Ministers and 17 per cent took place in States which have UPA Chief Ministers. Sir, this is your own Governmental data as far as crackdown on hoarders is concerned. But, you have turned a blind eye on the data and you start saying, 'well, the States are not co-operating. The States need to come down more heavily as far as hoarders are concerned.'

Sir, you also, now, say that the sugar industry is also in a strange kind of crisis of its own. We failed to understand, as far as sugar is concerned, if you anticipated the shortages, then either you have stocks in readiness, or, you rely on imports. What kind of policy manipulation taking place as far as sugar industry was concerned? The mill-owners interests are also very large. They

also find their way into Governmental thinking. So, the entire change of legal framework, which you have brought about on account of which this House was adjourned once or twice during the last Session, was a policy which the Government was bringing to do away with the State Advisory Prices and replace it with FRP essentially to help sugar mills. You export 48 or 49 lakh tonnes of sugar out of this country at Rs. 12.5 per kg and you import back at Rs. 36! Obviously, this is going to have its impact on prices. Sir, on 15th February, 2010, you allowed export of 10,000 tonnes of sugar to Europe when there is scarcity in the market, because you have an international commitment. It is only when noise is made in the media you have realised that we are going through a phase of shortage, we cannot comply with that international obligation and you cancelled it. But, honestly, what the Congress Sandesh says is a question which every hon. Member of this House must ask, 'Was there no co-ordination between the Prime Minister Office and the various Ministries of this Government? When we are passing through a major sugar crisis and no let down in the sugar prices is likely over the next few months even to comply with international obligations, how have you picked a period of shortages and say 10,000 tonnes more will go to the Europe?' If you cancelled it yesterday, and this obligation could be deferred to a period till we have surplus, well, this should have struck somebody on 15th February this year itself. I have given to understand that almost 9 lakh tonnes of sugar is lying at Kandla and other different ports and awaiting for processing. I would be glad if the hon. Minister tell us if they are going to be used to flood the market in order to bring down the prices as far as sugar is concerned.

I have now found an argument being advanced that we are a pro-farmer Government and, because we repeatedly increase the MSP more than what previous Governments have done, the MSP increases have resulted in this new burden as far as consumers are concerned.

The MSP increases are intended to compensate the farmers

because the cost of fertilizers is going up, the cost of power is going up, the cost of petrol is going up, the cost of diesel is going up, his cost of living is going up. Therefore, the farmer has to be compensated. But the long-term impact of increase in MSP is not what the Government, now, seems to be arguing. And, the MSP increase, in the short run, can result in the increase of prices, as far as consumers are concerned. But once MSP increases are given and a particular crop cultivation is made attractive, the acreage of cultivation of that crop increases and the increased production lead to drop in prices. So, if you increased prices 5 years or 6 years ago, as far as MSP is concerned, in the immediate short-term an MSP increase may contribute to an increase in prices, but in the long-term an MSP increase has to result in increased acreage of that particular crop and, therefore, brings the prices down, as far as that crop is concerned. The MSP increases have been made by repeated Governments. They have taken place now also. And, the farmer, in accordance with the cost of living and the cost of various inputs has, now, to be compensated.

The difficulty is not merely that the Government has run out of the ideas as to how to deal with the situation, but it has also become a little insensitive. You need Ministers, you need spokesmen of the Government who come and assuage the feelings of the people that they are attempting, these are the difficulties, these are the international prices, and so on and so forth. But you say that consumption patterns have changed! People are eating more! People are no longer starving!

Earlier also we had Food for Work Scheme and you had Anytodaya scheme for distribution of ration at extremely cheap rates to the weaker sections of the society. Therefore, the same people, who are now getting the benefit of the NAREGA Scheme, were also earlier getting the benefit of Food for Work Scheme and other schemes of the Government. Therefore, to say that you had societal-friendly schemes and suddenly that has resulted in shortage, I don't think is sensitive enough on the part a Government to say that.

Sir, then, the oil prices also increased. Well, in the last few months, as far as oil price increases are concerned, most of it had been absorbed by the oil companies. It has not yet been translated to have its impact as far as the consumers are concerned. But the Government must bear in mind one fact that in the current duty structure that we have, as far as oil prices are concerned, every increase in global oil prices, which is, then, eventually transferred to the consumer, a different enrichment of the Government is also taking place. So, in a place, like Delhi, when you start adding various kinds of duties, you will have an excise duty of 33 per cent. So, if the global prices go up from 50 dollars to 80 dollars, there is five upon eight increase as far as excise duty collection of the Government is concerned. Every 5 that you collected in terms of excise duties goes up to 8. The custom duty increases also go up, though the custom duty component duty itself is marginal. The sales tax being collected by the States, in Delhi it is 16.7 per cent, also increases. Therefore, when the prices are increasing, at least, in terms of total volume, keep the increase as revenue neutral as far as the State is concerned; that is, irrespective of the increase the Government gets the same amount of revenue, as far as oil is concerned. But if the Government's quantum of revenue also increases because of percentage increase, then, the consumer is hit in two ways. He pays more for his petrol, diesel and kerosene oil. The Government also stands to earn more because the percentage of duty being the same, and not being rationalised, also goes up and, then, the impact of this, besides on direct purchase of oil, on all other commodities is also going to increase.

So, the consumer is being hit in different ways as far as this is concerned. So, the Government has to be more sensitive and say, 'Well I won't have any unjust enrichment of profiteering as far as the increase of oil is concerned; I will be revenue-neutral and earn the same amount of revenue, irrespective of the increases in the prices of oil.' But the Government doesn't have that policy.

Finally, Sir, do the Government's statistics which are regularly

released to us also reflect the true picture as far as price rise is concerned? When I say that Wholesale Price Index goes up by 8.56 per cent, today the gulf between the CPI and the WPI, the Consumer Price Index and the Wholesale Price Index, has widened. The Reserve Bank itself says -- and I just quote what the Reserve Bank told the Parliamentary Committee. Sir, I am quoting, "Inflation assessment has become increasingly complex in recent times due to large divergence between the WPI inflation and various CPI inflation measures." Then, they go on to further add, "However the divergence between inflation rates of WPI and CPI has widened in the recent period and the WPI inflation turning negative for a few months even when the Consumer Price Index inflation was in double digits." So, when every week we were being told that inflation is negative and this is a great achievement of the Government in the slowdown period, the Consumer Price Index, the Reserve Bank says, was actually in double digits. That is the real impact of what the consumer has to pay. That is how the consumer is adversely affected and therefore the Reserve Bank says that in the last few years, the WPI and the CPI are converging. Now, we do find that you just cannot rely on one measure of inflation. The main reason is that the WPI does not have that much impact on food as the CPI has. Secondly, the WPI does not include service sector which is included in the CPI. So, there is no point us being confronted week after week with a price index which doesn't reflect the cost of food or doesn't entirely reflect the cost of food because for the average citizen that is the first requirement as far as food is concerned. So, this 8.56 per cent increase, which will become double digit by next month, is entirely on paper, if not fictional. The real price impact of this may be almost one-and-a-half to two times of that index. Now, a large number of countries in the world, in the last Session we were told almost 156 countries, have converged this into a Consumer Price Index because that is the real reflector as far as the price situation is concerned and the Government must seriously consider having one price index which actually gives the factual situation, rather

than give us the a fictional figure week after week which actually tells the consumer that prices have come down; but nobody is really willing to come out and face the reality that that figure is inaccurate.

Sir, the factual situation has worsened since we last discussed this. The Government cannot plead that 'there are alibis, there are global factors; there are shortages; I am unable to handle.' The Government has to act. If Governments can't act, the Governments must perish. The price situation is one area where the Governments must act and the Governments can't plead this kind of helplessness as far as the price situation in the country is concerned, and, Sir, it is precisely for this reason that we are extremely grateful to you for having allowed this debate ahead of other scheduled items on our agenda because this is one area -- which the entire Opposition, and, I am sure, there are many friends in the UPA also who think alike -- where the average citizen of this country is being almost driven to the wall where his family budgets don't match and, therefore, we expect the Government to come out with some action and for a long-term dealing to, at least, conceive coming out with some kind of a food price management policy, rather than just depend upon natural and international cycles for the prices themselves to come down.

Sir, if there is a single largest failure, as far as this Government is concerned, it is its management of the food prices. And, we in this House will be failing in our duties if we did not draw the attention of the Government to this one glaring failure. I am grateful to you, Sir. ■

सारांश

आदर्श स्थिति यह होती कि हम एक ऐसे प्रस्ताव के तहत बहस करते, जिसमें मतदान का प्रावधान होता। संसद को बहस की सीमाओं से दूर जाना चाहिए। देश में मूल्य स्थिति को सुलझाने के बारे में सरकार को संसदीय मत संग्रह कराना चाहिए। किंतु क्योंकि सरकार ऐसा करने की अनिच्छुक है अतः मूल्यवृद्धि से जूझने में सरकार की संवेदनहीनता तथा अक्षमता को उजागर

करने के लिए हम सदन के मंच का उपयोग करना चाहते हैं।

सरकार आर्थिक प्रबंधन के बारे में गंभीर नहीं है। कल का रेल बजट जो इस सत्र के अर्थ संबंधी कार्यक्रमों में से सर्वप्रथम है उससे देश को केवल हास्यास्पद राहत पहुँची है। रेलमंत्री स्पोर्ट स्टेडियम, मिनरल वाटर बोटलिंग प्लांट, मेडिकल संस्थाओं और भारत-बांग्लादेश संबंधों आदि के बारे में चिंतित थीं न कि अपने मूल कार्यक्रमों के बारे में। मुझे टाटा स्टील का वह प्रोमो याद आता है, जिसमें कहा गया था, "हम भी इस्पात निर्मित करते हैं"। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय इस स्थिति से जूझने में असहाय हो गया है? 'कांग्रेस संदेश' के संपादकीय में एक स्वीकारात्मक वक्तव्य छपा है, जिसमें कहा गया है, "गठबंधन सरकारों में प्रधानमंत्री कार्यालय तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ रहती हैं"। सदैव से ही मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। मंत्रिमंडल अलग-अलग दिशाओं में जाकर काम नहीं कर सकता है। कोई भी सरकार इस आधार पर असहायता व्यक्त नहीं कर सकती है कि मंत्री प्रधानमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पत्रिका 'राष्ट्रवादी' के संपादकीय में टिप्पणी की गई है कि यदि लोग चीनी नहीं खाते हैं तो वे मर या व्यथित नहीं हो जाएंगे। सत्ता में बैठे लोगों में ऐसी संवेदनहीनता है। उनकी तुलना Marie Antoinette की इस टिप्पणी से की जा सकती है – "यदि उन्हें रोटी नहीं मिलती है तो वे केक खाएँ"।

सरकार का रवैया

इस सरकार का मूल्य स्थिति पर सामान्य रवैया घोर अनर्थकारी रहा है। क्या सरकार के पास इस बारे में कोई चिंतन नहीं बचा है अथवा इस स्थिति से कैसे निपटा जाए इस बारे में कोई विचार नहीं बचा है? क्या सरकार अपनी नाक से आगे नहीं देख सकती है तथा अभाव का पूर्व अनुमान नहीं लगा सकती है कि उसे बाजार पर अंकुश रखने के लिए आयात या स्टॉक का सहारा लेना है? क्या कोई नीतिगत हेरा-फेरी की गई है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि हुई है अथवा सरकार इस स्थिति से निपटने में असहाय महसूस कर रही है और अपनी विफलता को छिपाने के लिए बहाने ढूँढ रही है? ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने कुछ न करने का और बाजार को स्वयं अपनी समस्या सुलझाने तक का इंतजार करने का रवैया अपना लिया है।

वास्तविक स्थिति

थोक मूल्य सूचकांक वास्तविक मूल्य स्थिति को अभिव्यक्त नहीं करता

है। थोक मूल्य सूचकांक में 8.56 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की स्थिति दर्शायी गई है। औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 14.97 प्रतिशत और कृषि कर्मियों के लिए 17.41 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। खाद्य मूल्य सूचकांक 17 से लेकर 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। हम अभी-अभी मंदी की स्थिति से उबरे हैं। क्रय शक्ति कमजोर है। **Slow Down** सामान्यतः मंदी की स्थिति अथवा मूल्यहास दर्शाता है। **Downturn** के दौरान भारत ने खाद्यमूल्य स्फीति देखी थी। हम निश्चित रूप से द्विअंकीय मुद्रास्फीति की तरफ बढ़ रहे हैं। यह मुद्रास्फीति संप्रग सरकार द्वारा उपभोक्ता पर थोपा गया अनधिनियमित कर है। फुटकर दुकानों पर मूल्य मंडियों से कहीं अधिक हैं। वास्तविक मूल्य दर्शाता है कि दिसम्बर, 2009 में प्रसंस्करित खाद्य के मूल्य में 27 प्रतिशत की, आलू के मूल्य में 70 प्रतिशत की, प्याज के मूल्य में 45 प्रतिशत की, दाल के मूल्य में 45 प्रतिशत की तथा खाद्यान्नों आदि के मूल्यों में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार वर्तमान दाल नीति के बारे में सचिन तेंदुलकर की नकल कर रही है। दाल मूल्यों ने शतक बना दिया है, चीनी के मूल्य पहले ही अर्धशतक बना चुके हैं। अधिक सक्रियता दिखाने और स्थिति से निपटने के बजाय सरकार झूठे बहाने ढूँढ रही है।

सूखा

सरकार का दावा है कि असमान मानसून के कारण खरीफ की फसल में 18 मिलियन टन की कमी आई है। यह अब तक मूकदर्शक क्यों बनी हुई है। 2002 के सूखा के दौरान खाद्यान्नों में 40 मिलियन टन की कमी हुई थी। बाजार 60 मिलियन टन खाद्यान्नों से पटा पड़ा था और 2002-2003 में मुद्रास्फीति को 3.4 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था। आज यह 2 अंकों में पहुंच गई है।

वायदा बाजार

अधिशेष की अर्थव्यवस्था में ही वायदा बाजार तथा वस्तु विनिमय का सहारा लिया गया था। क्या संप्रग सरकार को अभाव की अर्थव्यवस्था में इस नीति की पुनरीक्षा नहीं करनी चाहिए थी? स्पष्टतः केवल 1 प्रतिशत actual delivery के साथ वस्तु विनिमय पर यदि 4.5 लाख करोड़ का वायदा बाजार हो तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की आशाएं पैदा हो जाएंगी।

राज्य सरकार

केन्द्र द्वारा राज्यों पर – विशेषतया प्रतिपक्ष द्वारा शासित राज्यों पर आरोप लगाना अनुचित होगा। जमाखोरी के विरुद्ध कुल जितनी भी सख्त

छापेमारी की गई है उनमें से 83 प्रतिशत गैर-संप्रग शासित राज्यों में हुई हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह केवल 17 प्रतिशत हुई है। यह मुख्यमंत्रियों के सामने प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट हुआ था।

चीनी अर्थव्यवस्था

स्पष्टतः सरकार के चीनी मूल्य निर्धारण में मिल मालिकों की बात मानी गई है। राज्य परामर्शित मूल्यों को त्यागने की पूरी अवधारणा किसानों को नुकसान पहुंचाने और मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए अपनाई गई थी। 49 लाख टन चीनी 12.50 रूपए प्रतिकिलो ग्राम की दर से निर्यात की गई थी, पर देश में चीनी 36 रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर आयात की गई है। 15-02-2010 को 10 हजार टन चीनी के निर्यात की अनुमति क्यों दी गई, जबकि अर्थव्यवस्था अभाव का सामना कर रही है। गुजरात के बंदरगाहों पर पड़ी 9 लाख टन चीनी अभी भी उपभोक्ता के उपयोग के लिए प्रसंस्कारित होने की प्रतीक्षा कर रही है ? चीनी के मूल्यों में वृद्धि नीति में हेरा-फेरी का परिणाम है।

मूल्यवृद्धि में न्यूनतम समर्थन मूल्य का इजाफा

सरकार ने बार-बार यह झूठा बहाना किया है कि संप्रग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप मूल्यों में इजाफा हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के पीछे यह आशय होता है कि उससे किसानों को उर्वरक लागत, परिवहन लागत, ईंधन मूल्य, बिजली लागत और निर्वहन लागत के विरुद्ध राहत मिल सके। कुछ फसलों को प्रोत्साहन देने का भी इसका आशय होता है। संक्षेप में इससे मूल्य बढ़ सकते हैं परंतु दीर्घावधि में कुछ फसलों के बुआई क्षेत्रों को बढ़ाकर अधिक उत्पादन मिलता है तथा कीमतें कम हो जाती हैं।

नरेगा के कारण उच्च उपभोग पैटर्न

इस देश में सदैव ही कार्य के बदले अनाज तथा अंत्योदय स्कीम के अधीन दुर्बल वर्ग को राशन का वितरण होता रहा है। इन इमदादों को भुखमरी दूर करने और दुर्बल वर्गों को खाने का अधिकार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। क्योंकि इन्हें अब नरेगा स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया है इसलिए इनके परिणामस्वरूप अभाव नहीं हो सकता।

तेल के मूल्यों में वृद्धि

तेल के मूल्यों में वृद्धि को अभी उपभोक्ताओं पर नहीं लादा गया है। पिछले कुछ महीनों में बाजार में इसके प्रभाव को महसूस नहीं किया गया

है। स्पष्टतः इसके कारण मूल्यवृद्धि नहीं हुई है। फिर भी यदि अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्य ऊंचे हो जाते हैं तो pricing revenue को neutral रखने के लिए duty components को युक्तियुक्त बनाना होगा। Excise duty, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क तेल के मूल्यों में आधे से अधिक योगदान करते हैं। यदि कर संरचना समान रहती है तो वैश्विक मूल्यों में प्रत्येक वृद्धि राज्य के राजस्व संग्रह को अनुचित रूप से बढ़ाती है। यदि राज्य ने revenue neutral policy अपनाई होती तो मूल्यों का प्रभाव समत हो सकता था।

थोक मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

थोक मूल्य सूचकांक का सेवाओं तथा काफी अधिक संख्या में खाद्य वस्तुओं में असर नहीं होता है। इससे बाजार में मूल्यों की वास्तविक वृद्धि की जानकारी नहीं मिलती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वास्तविकता के अधिक निकट है। दोनों के बीच भारी अंतर है। विश्व के अधिकांश देशों ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपना लिया है तथा थोक मूल्य सूचकांक को त्याग दिया है। यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय उपभोक्ता भी कुछ काल्पनिक या अवास्तविक आंकड़ों के बजाय मूल्य वृद्धि के वास्तविक प्रभाव को महसूस करता है।

मूल्यों में नियंत्रण की सीमा से बाहर वृद्धि हुई है। सरकार आपूर्ति पक्ष के अभावों की पूर्व आशा करने में विफल रही है। सरकार उपभोक्ताओं को विशेषकर खाद्यों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि करके भारी कष्ट पहुंचाती जा रही है। सरकार को शासन करने का मूल मंत्र सीखना चाहिए – कार्य करो या हट जाओ।